

सम्पादकीय

व्यावहारिक समाज में पहेली बनी योग्यता का चुनाव

महाभारत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि योग्य कौन है और यदि कोई योग्य है तो उसे समाज द्वारा कैसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। समूचे विश्व में सामाजिक संघर्ष की एक बड़ी लड़ाई इसी सवाल के ईंट-पिर्ट ही धूमती है। वर्ष 1958 में ब्रिटिश समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ माइकल यंग ने एक पुस्तक लिखी- द राइज आफ मेरिटोक्रेसी। इस पुस्तक में उन्होंने एक ऐसे समाज की बात कही जहां व्यक्तियों को पढ़, सत्ता और आर्थिक संपत्ति उनकी योग्यता के आधार पर प्राप्त होगी। पश्चिमी देशों में आज भी इस तरह के मंतब्य के आधार पर योग्यता को मौका दिया जाता है। लेकिन इससे इतर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि योग्यता का पैमाना कैसे तय किया जाए कि कौन योग्य है और कौन नहीं। योग्यता का निर्धारण करते समय प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहे अवसरों की समानता, सामाजिक-आर्थिक और लैंगिक असमानता के स्तर को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर ही नहीं मिला, तो क्या वह अयोग्य माना जाएगा? हमारे जटिल समाज में विविध जाति, प्रजाति, धर्म, बोली, भाषा व लिंग पर आधारित तथ्यों और इन तथ्यों से जुड़ी असामानता से भी किसी व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण होता है, इस बिंदु को नकारा नहीं जा सकता। भारतीय संविधान के निर्माण इस बात से बहुत अच्छे से अवगत थे, इसलिए उन्होंने संविधान का निर्माण करते समय अवसरों की समानता को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक व आर्थिक न्याय की संकलना को भी पूरा स्थान दिया। निश्चित तौर पर समाज में सामाजिक व आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति की अगली पीढ़ी को जो अवसर प्राप्त होगे, वे अवसर वंचित समुदाय की अगली पीढ़ी के लिए दूर की कौड़ी होंगे। ऐसे में सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए प्रयास करना किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए एक अनिवार्य पहलू है और कोई भी सभ्य समाज इस बिंदु को नकार नहीं सकता। वैसे हम दश-दुनिया के बड़े सफल नामों को देखें तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साधारण पृष्ठभूमि से ही आगे आए और अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। लेकिन ऐसे लोग गिनती के हैं और बड़ी संख्या में ऐसे ही लोग ज्यादा सफल हैं जो पीढ़ीगत तौर पर मजबूत स्थिति में रहे हैं। ऐसे में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सामाजिक असमानता को नजरअंदाज कर केवल योग्यता मूलक समाज की परिकल्पना एक आदर्श राज्य की परिकल्पना है, जहां समाज में व्याप्त असमानताएं समाप्त हो चुकी हों। लेकिन किसी जटिल समाज में सामाजिक न्याय ही भेदभाव का रूप न बन जाए और योग्यता के विकास को न रोक सके, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए। भारत वर्त संदर्भ में समाजशास्त्रियों का एक वर्ग यह भी मानता है कि यहां सामाजिक व आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के क्रम में पिछेपन की दौड़ भी प्रारंभ हुई है। लोकतंत्र में सामाजिक व आर्थिक न्याय का लक्ष्य असमानता को दूर करना था, लेकिन इसका एक विपरीत प्रभाव यह भी हुआ कि लोकतंत्र में संसाधनों में पहुंच स्थापित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समूह स्वयं को वंचित श्रेणी में लाना चाहते हैं। इस असमानता के स्थायी चक्र को तोड़ कर सामाजिक व आर्थिक न्याय का विरोधी होने का आरोप कोई भी नहीं लेना चाहता। भारत में लोकतंत्रिक तंत्र का यह एक नकारात्मक प्रभाव है जो योग्यता के चुनाव में प्रभावी है। लेकिन एक अन्य सकारात्मक पहलू भी है, यूमंडलीकरण से उपजी बाजारी अर्थव्यवस्था और इंटरनेट मीडिया के उदय के बाद अब योग्यता के प्रदर्शन के लिए अवसर पहले से ज्यादा बेहतर है और यहां किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि से ज्यादा सफलता की गांठटी इस बात पर है कि उसके पास आइडिया क्या है और क्या वह आइडिया बाजार की जरूरतों को पूरा कर सकता है। क्या वह आइडिया लोकप्रियता हासिल कर सकता है और यदि ऐसा है तो कोई मूंगफली बेचने वाला भी रातों-रात इंटरनेट मीडिया सनसनी बन सकता है। बाजारवादी व्यवस्था की गलाकाट कमियों के बीच में यह एक बड़ा मौका भी है। युवाओं को बाजार से पैदा हो रहे इन मौकों का भरपूर फायदा उठाना चाहिए और अपनी योग्यता को साबित करना चाहिए।¹ और वह अपनी सक्षम आय सीमा के भीतर ऐसा कर सकता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता और सभ्य लोकव्यवस्था इस मूल्य को स्थापित करने का प्रयास करती है कि समाज में असमानता का स्तर घटे और सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से पर्यावरण पर व्यापक दुष्प्रभाव की आशंका

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियारों से संबंधित अपनी टीम को हाई अलर्ट मोड पर रखने का आदेश दिया है। यदि दुर्भाग्यवश इस युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग किया गया तो इसका दुष्प्रभाव समूचे विश्व पर होगा। परमाणु बमों के विस्फोटों से 1.6 से 3.6 करोड़ टन थूले और राख उड़कर वातावरण में कई किमी ऊपर तक लंबे समय के लिए छा जाएगी जिससे धरती पर पड़े गाली सूर्य की रोशनी में 20 से 35 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। ऐसे में धरती का तापमान दो से पांच डिग्री सेल्सियस तक कम होने की आशका जर्ताई जा रही है। इससे बारिश में 15 से 30 प्रतिशत कमी हो सकती है जिससे फसलों के उत्पादन पर असर की आशंका बढ़ जाएगी। नतीजन भुखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। सूर्य से निकलने वाली पराबैगनी किरणों से धरती की रक्षा करने वाली ओजोन परत पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो जाएगी। परमाणु विकिरण और आणिक तत्वों के कहर से यदि कोई जीवित रहा तो उसे पराबैगनी किरणों समाप्त कर देंगी। कुल मिलाकर युद्ध से करोड़ों वर्षों में विकसित मानव सभ्यता तबाह हो जाएगी। आज विश्व में 50 हजार से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और प्रत्येक हथियार की क्षमता जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे किसी भी शहर को एक झटके में विनाश करने के लिए उपयुक्त है। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार इन हथियारों से समूची धरती को दर्जनों बार मिटाया जा सकता है। परमाणु बम में सबसे अधिक खतरनाक हाइड्रोजन बम है, जिसकी विनाशक क्षमता लगभग दो करोड़ टीएनटी आंकों की गई है। मालूम हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने जो सबसे बड़ा बम (और परमाणु) गिराया था, उसकी विधंकसक क्षमता लगभग 20 टीएनटी थी। साथ ही जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम इससे करीब 600 गुना ज्यादा प्रभावी था। ऐसे में आसानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मात्र एक हाइड्रोजन बम धरती पर कितनी तबाही मचा सकता है। अपनी व्यापक विधंकसक क्षमता के कारण ये परमाणु बम दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ते हैं। परमाणु विकिरण के कारण पुनः उत्पन्न होने वाली गामा किरणें पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली शारीरिक अक्षमता और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को पैदा करती है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1945 के बाद से अमेरिका ने हर नौ दिन में एक के औसत से परमाणु परीक्षण किया है।

यूक्रेन पर पुरुषों का विपरीत है। रूस की माने तो यूक्रेन पर हमला इसलिए जरूरी हो गया था, क्योंकि वह अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों के हाथों में खेल रहा था और इसके चलते उसकी अपनी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। यह सही है कि यूक्रेन अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन

मौजूदा दौर में जनमत निर्माण में पश्चिमी मीडिया के वर्चस्व को तोड़ना अब और जरूरी हो गया है

में उसकी सैन्य कार्रवाई पर विज्ञापन चलाने को लेकर रोक लगाई थी। जवाब में फेसबुक ने पूरे यूरोपीय संघ में रूसी राज्य मीडिया आउटलेट आरटी और स्युतनिक को ब्लाक किया है। गूगल ने भी रशिया टुडे और स्युतनिक के यूट्यूब चैनल को ब्लाक कर दिया है। अमेरिका और इंग्लैण्ड में ऐसी

सहयोगियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। उसी के साथ जनमत बनाने का खेल भी चल रहा है। शुक्र है कि मुक्त इंटरनेट मीडिया हमारे बीच मौजूद है, जो सबकी बातें प्रमुखता से लोगों के सामने रख रहा है। वैसे भी कूटनीति में कोई भी फ़सले दो दूनी चार नहीं के प्रसार में इंटरनेट की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। पश्चिमी मीडिया के इस नजरिये का शिकार भारत भी रहा है। साल 2012 में असम में उत्पन्न समस्या और भारत के कई शहरों से पूवीत्तर के निवासियों का पलायन हुआ। सरकार ने इसके लिए इंटरनेट

बयान दिया कि अमेरिका इंटरनेट की आजादी के पक्ष में है। भारत सरकार मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखे। भारत को मानवाधिकार और इंटरनेट की आजादी का पाठ पढ़ाने वाले इस बयान को जरा इस तथ्य के संदर्भ में पढ़ें तो एक बार फिर अमेरिका का व्यावसायिक नजरिया स्पष्ट हो जाएगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था विकास केंद्रित हुई है। इसकी गति को बढ़ाने में इंटरनेट की बड़ी भूमिका है। इंटरनेट के अस्तित्व में आने के बाद से इस पर अमेरिकी सरकार, कंपनियों और प्रयोगकर्ताओं का अधिपत्य रहा है, लेकिन अब इसमें तेजी से बदलाव आ रहा है, जिसका केंद्र भारत, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और ब्राजील जैसे देश हैं। फेसबुक को अन्य देशों की क्षेत्रीय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों जैसे जापान की मिक्सी, रूस में वोकांटे से कड़ी टक्कर मिल रही है। सूचनाओं के प्रसार के साथ-साथ ये लोगों के व्यावसायिक रूप से भी प्रभावित कर रही हैं। जैसे फेसबुक का मतलब महज सोशल नेटवर्किंग नहीं है, बल्कि यह विज्ञापन, मीडिया और नए रोजगार के निर्माण से भी संबंधित है। जाहिर है सूचना क्रांति ने लोगों के मूलभूत अधिकारों और मानवाधिकारों को एक बड़े बाजार में भी तब्दील कर दिया है। जनसत्त निर्माण इससे भी प्रभावित हो रहा है।



का सामना ले खुले जाना था, पर
पहली बार किसी वेबसाइट से आई
समर्पित रीती और अखबारों की
खबरों का आधार बनी। आज
अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन समेत
तमाम देश रूस और उसके

भाइकाऊ पर जला अपवाहन। आइ
कार्रवाई करते हुए 245 वेबस्टीटों
को ब्रॉक कर दिया। सरकार के
इस फ़िसले के बाद अमेरिकी विदेश
मंत्रालय की तक्तालीन प्रवक्ता ने

खतरनाक मोड़ लेता यूक्रेन संकट, विश्व शांति के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बढ़ रहा खतरा

यूक्रेन पर हमला करने के करीब दस दिन बाद रूस जिस तरह कुछ घंटे के लिए युद्ध विराम के लिए राजी हुआ, उससे वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता करता तो दिखा, लेकिन यह नहीं कहा नाटो में शामिल होने को तैयार था, लेकिन केवल इस आधार पर उस पर हमले का औचित्य नहीं बनता। यूक्रेन पर रूस के हमले से यह साफ़ है कि उसने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से को भारत का यह रवरेया रास नहीं आया, लेकिन यूक्रेन संकट पर भारत का टटस्थ रहना समय की मांग है। यही कारण रहा कि विदेश मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में विपक्षी दलों ने

स्प्रभुता और अखड़ता का भी सम्मान आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से अपनी बातचीत में युद्ध रॉकने की बात भी कर चुके हैं। वास्तव में भारत ने प्रारंभ से ही कूटनीति के जरिये समस्या के समाधान पर जोर अपने छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वापसी। इसके लिए रूस और यूक्रेन, दोनों का सहयोग जरूरी है। दशकों की करीबी मित्रता और रक्षा खरीद के लिए रूस पर निर्भरता के बावजूद भारत ने न केवल रूस को संयुक्त

शामल है, लोकन यूक्रेन के राष्ट्रपति इतने मात्र से संसुष्ट नहीं। पुतिन इस समय जैसे आक्रामक रूप में दिख रहे हैं, वह दुनिया के प्रति उनके बेरपवाही भरे रुख का ही परिचय करता है। ऐसे में यह



सरकार के रुख का समर्थन किया। भारत ने भले ही रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर मतदान न किया हो, लेकिन उसने रूस को यह संदेश देने में सकोच नहीं किया कि वह सामरप्रयासों का संतुलित तैरां

दिया है। भारत के तटस्थ रुख का यह मतलब नहीं कि वह रुस के साथ खड़ा है। इस संदर्भ में भारत ने अपना जो पक्ष रखा, उसे अमेरिका, फ्रांस आदि ने समझा भी है। प्रश्न के लिए दूसरा सामाजिक संघर्ष है।

ਪਿੰਚ ਪਗ ਪਿੰਚ ਬਢ਼ਾਂ ਪਾਲਾ

यक्रेन पर पुतिन के आक्रामक दांव ने भारत के समक्ष बढ़ाई संतुलन साधने की चूनौती

यूक्रेन पर रूस के हमले ने भारत के लिए कई चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इन चुनौतियों का संबंध आर्थिक, सामरक, कूटनीतिक एवं मानवतावादी जैसे पहलुओं से है। रक्षा साजोसामान की आपूर्ति के लिए भारत अभी तक रूस पर निर्भर है। इस बीच अमेरिका के साथ भी भारत के व्यापक हित ज़ुड़ते गए। बहरहाल रिश्तों की ये कठियां केवल भारत ही नहीं, बल्कि इन दोनों देशों और कई नाटो देशों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में भारत का कूटनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए रूस और अमेरिका दोनों द्वारा लाइंग किया जाना स्वाभाविक है। जैसे-जैसे यूक्रेन में रूस की जंग तेज होती जा रही है, वैसे-वैसे रूस और नाटो देशों के बीच कूटनीतिक युद्ध भी तल्ख होता जा रहा है। इस दौरान भारत की पहली प्राथमिकता हजारों छात्रों सहित अपने नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी है। युद्ध के बीच यह कभी आसान नहीं रहता। हजारों छात्र भारत लौट आए हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि सभी की सकाशल वापसी होगी। यह दुखद है कि कर्नाटक के एक छात्र की रुसी गोलाबारी में जान चली गई। वही एक छात्र का उपचार के दौरान निधन हो गया। हाल-फिलहाल 3 अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति यूक्रेन के साथ है। दरअसल इस दौर में किसी देश का दूसरे देश पर आक्रमण करना अस्वीकार्य है। अपने सामरिक हितों को अनन्देखा करने के लिए अमेरिका एवं यूरोपीय देशों से रूस की वाजिब शिकायतें थीं। वे रूस की पश्चिमी सीम पर स्थित देशों को नाटो सदस्य बनाने में लगे थे। इसे लेकर रूस ने यूक्रेन के मामले में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिस देश के साथ उसका गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। फिर भी ऐसे तमाम उकसावे के बावजूद यूक्रेन पर रूसी हमले को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस हमले ने नाटो देशों के समक्ष दुविधा उत्पन्न कर दी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि एक तो रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। दूसरा यह कि दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा भी उसके पास है। स्पष्ट है कि नाटो देश रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन में अपनी सेनाएं नहीं भेज सकते, क्योंकि इससे न केवल युद्ध के लंबा खिंचने, बल्कि परमाणु शक्तियों के सक्रिय होने से जोखिम और बढ़ जाएगा। ऐसे संघर्ष के लंबा खिंचने की कल्पना ही सिहरन पैदा कर सकती है। वहीं यह बात भी उतनी ही खरी है कि नाटो इस आक्रमण को अनन्देखा नहीं कर

सकता है। इसीलिए उसने त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई है। पहली यही कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से रूस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाना। दूसरे, यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति सहित हरसंभव सहयोग देना। तीसरा, रूस पर कड़े वित्तीय एवं अन्य प्रतिबंध लगाना ताकि उनसे कुपित रूसी नागरिक पुतिन के खिलाफ भड़क जाएं। जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं उसमें तय है कि यूक्रेन के राष्ट्रपृष्ठ जेलेंस्की की सरकार को भले ही कितना समर्थन मिले, लेकिन रूसी आक्रमण के आगे उनका प्रतिरोध लड़े समय तक नहीं ठिकने वाला। इसका अर्थ यही होगा कि यदि संपूर्ण यूक्रेन नहीं तो उसका अधिकांश हिस्सा रूसी कब्जे में चला जाएगा। फिर पुतिन वहां अपनी कठपुतली सरकार बिठा देंगे। इसके बाद नाटो यही सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि रूसी समर्थन गली ऐसी सरकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता न मिलने पाए। साथ ही साथ यह संगठन रूस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने के अलावा प्रतिबंधों का शिकंजा और कसता जाएगा। यह तस्वीर काफी कुछ इस पर निर्भर करेगी कि यूक्रेनी अपनी जमीन पर किस प्रकार निरंतर विरोध कर पाएंगे। इस परे परिदृश्य के आकलन में तमाम अनिश्चितताएं जुड़ी हैं, जिनका भारत सहित सभी देशों पर प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में रूस की खुलकर आलोचना करने के लिए अमेरिकी दबाव और रूस के साथ अपने रिश्तों को सुरक्षित रखने की दिशा में भारत ने अभी तक सधा हुआ रुख अपनाया है। भारत की यह सतर्कतापूर्ण नीति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों की बैठकों में देखी जा सकती है। चूंकि भारत संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर

मतदान से अनुपस्थित रहा तो इसका यह आकलन करना गलत होगा कि भारत की स्थिति स्थैतिक है। भारत अपने बयानों से अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। ऊपरी तौर पर यह दिख सकता है कि भारत रूसी हमले पर आए प्रस्तावों पर मतदान से दूर रहा। इसे रूस के प्रत्यक्ष समर्थन के रूप में देखना गलत होगा। यूक्रेन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर सुरक्षा परिषद में 21 फरवरी से चार मार्च के बीच कुल 47 छैंडैंडों हुई। इन सभी बैठकों में भारत ने इसी बात पर जोर दिया कि विवादों का निपटारा संवाद, नार्ता और कूटनीति के जरिये किया जाए। उसने यह भी कहा कि सैन्य टकराव से बचना होगा। सुरक्षा परिषद की 21 फरवरी को हुई बैठक रूस द्वारा यूक्रेन के दो अलगावावादी प्रांतों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान करने के बाद हुई थी।

